



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India



दिनांक : 09 जून 2025

निदेश

विषय: दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) के अनुसार पोर्ट आउट विंडो के दौरान डीएलटी प्लेटफॉर्म पर लोकेशन रूटिंग नंबर (एलआरएन) को अपडेट करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत निर्देश।

फाईल संख्या: डी-27/1/(1)/2025-क्यूओएस (ई-16147)—चूंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है), जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके बाद "ट्राई अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, को अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय कार्यों का निर्वहन सौंपा गया है जैसे कि दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना आदि ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

2. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (v) और खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) दिनांक 19 जुलाई 2018 (जिसे आगे "विनियम" कहा जाएगा) बनाया है;

3. और जबकि उक्त विनियमनों के अध्याय III के विनियम 6 में यह अधिदेश दिया गया है कि प्रत्येक एक्सेस प्रदाता ग्राहक वरीयता पंजीकरण सुविधा (सीपीआरएफ) स्थापित करेगा और अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरे वर्ष 24 घंटे x 7 दिन के आधार पर सहायता प्रदान करेगा।

4. और जबकि विनियमों के खंड 7 में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक एक्सेस प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सक्राइबर द्वारा दर्ज या संशोधित प्राथमिकताओं को लगभग वास्तविक समय में (Near real time) और इस तरह से प्रभावी किया जाए कि चौबीस घंटे या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के बाद सब्सक्राइबर की प्राथमिकताओं के उल्लंघन में कोई वाणिज्यिक संचार की डिलीवरी नहीं की जाए या ऐसे संचार को अवरुद्ध किया जाए ;

5. और जबकि विनियमों की अनुसूची-II का खंड 6 आगे निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, वरीयताओं को पंजीकृत करने वाले ग्राहक के कम से कम निम्नलिखित विवरणों को रिकॉर्ड करने के लिए अपेक्षित कार्यों, प्रक्रिया और इंटरफेस के साथ वरीयता (डीएल वरीयता) के लिए डिस्ट्रीब्यूट

लैजर्स बनाएगा और उन्हें ऑपरेट करेगा. ग्राहक के वर्तमान सेवा नेटवर्क का लोकेशन रूटिंग नंबर (एलआरएन), जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा एक्सेस प्रदाता को सौंपा गया है और नए सेवा नेटवर्क के एलआरएन में परिवर्तन, यदि ग्राहक को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के दौरान पोर्ट-इन किया जा रहा है;

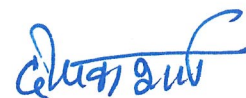
6. और चूंकि यह प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ मामलों में, पोर्ट-आउट विंडो के दौरान डोनर एक्सेस प्रदाताओं द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड लैजर सिस्टम में एलआरएन को अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नए सेवा नेटवर्क में ग्राहक द्वारा दी गई वरीयता को अपडेट करने का प्रयास विफल हो रहा है, जिससे न केवल उक्त विनियमन का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है और टेलीमार्केटर्स और एक्सेस प्रदाताओं के लिए परिचालन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं;

7. इसलिए, अब, प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ धारा 13 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) के प्रावधानों के अनुसार, सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश देता है कि वे:

(ए) सुनिश्चित करें कि पोर्ट-आउट किए गए ग्राहकों के लिए प्राप्तकर्ता नेटवर्क का लोकेशन रूटिंग नंबर (एलआरएन) डोनर एक्सेस प्रदाता द्वारा सफल पोर्टिंग लेनदेन के 24 घंटे के भीतर डीएलटी सिस्टम में अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाता है। नियमों की अनुपालना न किए जाने के कारण प्राप्त हुई शिकायतों को मासिक आधार पर भादूविप्रा को प्रस्तुत/सूचित किया जाएगा.

(बी) इस निदेश की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें उठाए गए तकनीकी कदमों, कार्यान्वयन के लिए समयसीमा और विनियम 17 के तहत उनकी कोड ऑफ ईथिक्स में किसी भी संबंधित परिवर्तन का संकेत दिया गया हो.

(सी) ग्राहक वरीयताओं, एलआरएन आदि से संबंधित सभी विनियामक और तकनीकी डेटा के लिए विभिन्न एक्सेस प्रदाताओं के डीएलटी प्लेटफार्मों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और समन्वय सुनिश्चित करना जारी रखें।



(दीपक शर्मा)

सलाहकार (सेवा गुणवत्ता-II)

सेवा में :

सभी सेवा प्रदाता